

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 25th March, 1988

No. 1/10/87-IMI&P.— The following draft of the rules further to amend the Punjab State Electricity Board Rules, 1959, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 78 of the Electricity (Supply) Act, 1948, is published, as required by sub-section (1) of that section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Irrigation and Power Department, Chandigarh, with respect to this draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Punjab State Electricity Board (Haryana—Amendment) Rules, 1988.

2. In the Punjab State Electricity Board Rules, 1959, in rule 5, in clause (b), for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(v) If a part time non-official member, he shall be paid a sum of Rs.1000/- per mensem in addition to the travelling allowances from the place of his residence to the Head-quarters of the Board or such other place where a meeting of the Board is held and back for the purpose of attending the meeting of the Board as admissible under rule 7 below. He shall also be entitled to draw daily allowance @ of Rs.75 per meeting or sitting. Further non-official members of the Board will be allowed incidental or mileage allowance, equivalent to the entitlement of class-I officers, if they are not being given any conveyance allowance.”

H. D. BANSAL,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Irrigation and Power Department, Chandigarh.

सिंचाई तथा विजली विभाग

दिनांक 25 मार्च, 1988

सं० 1/10/87-1 एम० आई० एण्ड पी०.—पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड नियम, 1959 को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 78 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करा है, उस धारा की उपधारा (1) द्वारा यथोपेक्षित उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद आक्षेपों तथा सुझावों सहित सरकार द्वारा नियमों के प्रारूप पर, यदि कोई हों, जो आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार सिंचाई तथा विजली विभाग, चण्डीगढ़ से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (हरियाणा—संशोधन) नियम, 1988 कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड नियम, 1959 में, नियम 5 में खण्ड (ख) में उप-खण्ड (V) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“यदि कोई अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य अपने निवास स्थान से बोर्ड के मुख्यालय अथवा ऐसे स्थान से जहां बोर्ड की बैठक होती है तथा नियम 7 के अधीन अनुसूच्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये उसे यात्रा भत्ते के अतिरिक्त 1000 रुपये की राशि का प्रति मास भुगतान किया जाएगा। वह 75 रुपये की दर पर दैनिक भत्ता प्रति बैठक लेने का हकदार भी होगा। आगे बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य को प्रथम वर्ग के अधिकारी की हकदारी के समान यदि उन्हें कोई बाहन भत्ता नहीं दिया गया है, आकस्मिक इयदा मील भत्ता अनुज्ञात होगा।”

एच० डी० बन्सल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा विजली विभाग, चण्डीगढ़।